Gustakhi Maaf Haryana

Pawan Kumar Bansal
Author & Journalist.
8882828301

OFFICE OF ADVOCATE GENERAL (AG), HARYANA NOT PERTAINS TO HARYANA

Claims CM Window.

Looks unbelievable, but it is true. In response to a complaint at Window by Punjab & Haryana High Court Advocate Pradeep Singh, he got response from the Window that No Action Required as the matter does not pertains to State (Haryana).!!!

On 13th June, 2023 Pradeep Singh has pleaded that cognizance should be taken on the issue of two different types of signatures as made by Pravindra Singh Chauhan, Advocate (P-2492/1999) i.e. one in the record of the Haryana Electricity Regulatory Commission (HERC), Panchkula where he served as Member (Legal) and other in the record of office of Advocate General, Haryana where he's currently working as Sr. Additional Advocate General. Pradeep has submitted proof of two different types of signatures.

In this case Window acted very quickly and surprisingly on the same very next day complainant was informed by the CM office in its report that — No Action Required as the issue does not pertain to our state. Even the formality of sending the said complaint to the office of the Advocate General, Haryana and the office of the Haryana Electricity Regulatory Commission, Panchkula for their comments was not completed in this case for the reasons best known and well understood to those running the CM Window.

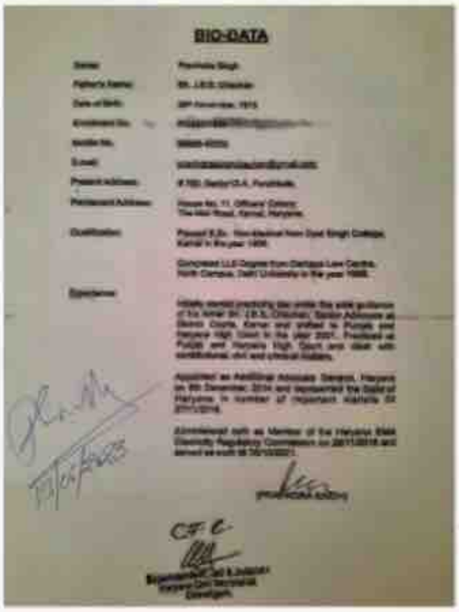

BIO-DATA

Tailpiece

Haryana Govt. has recently recommended the name of Pravindra Singh Chauhan, Advocate for appointing him as Judge of the Punjab & Haryana Court. " Gustakhi Maaf Haryana " congratulates Mr. Chauhan in advance.

Heading Sent by office of CM -Not pertaining to our State.

Sent by office of CM -Not pertaining to our State.

गुस्ताखी माफ़ हरियाणा

पवन कुमार बंसल

लेखक और पत्रकार

8882828301

मुन्नी बदनाम हुई डर्लिंग तेरे लिए सी एम विंडो बदनाम हुई न जाने किसके लिए ?

सीएम विंडो का शिकायतकर्ता को जवाब - एडवोकेट जनरल हरियाणा के दफ्तर से संबंधित जानकारी हमारे राज्य से ताल्लुक नहीं रखती।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के वकील प्रदीप सिंह ने तेरह जून को विंडो में शिकायत दर्ज कर मांग की थी

परविंदर सिंह चौहान द्वारा दो पदों के लिए अलग - अलग दकसत करने के मामले में एक्शन लिया जाये।

शिकायत में कहा की चौहान ने हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सदस्य (लीगल) रहते और एडवोकेट

जनरल हरियाणा के दफ्तर में सीनियर एडिशनल अधिवक्ता जनरल रहते अलग - अलग दकसत किये। उन्होंने इस बारे सबूत भी दिए। लेकिन इस मामले में विंडो ने गजब की फुर्ती दिखाई और अगले दिन ही प्रदीप को सूचित किया गया की चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जवाब आया है की इस मामले में कोई एक्शन नहीं बनता क्योंकि यह मामला हमारे राज्य का नहीं है।

इस मामले में विंडो ने इसे एडवोकेट जनरल ऑफिस और हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के दफ्तर में उनकी टिप्पणी के लिए भी नहीं भेजा।

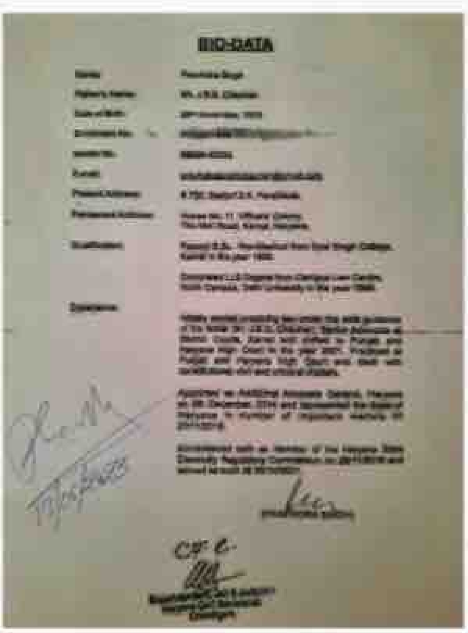

BIO-DATA

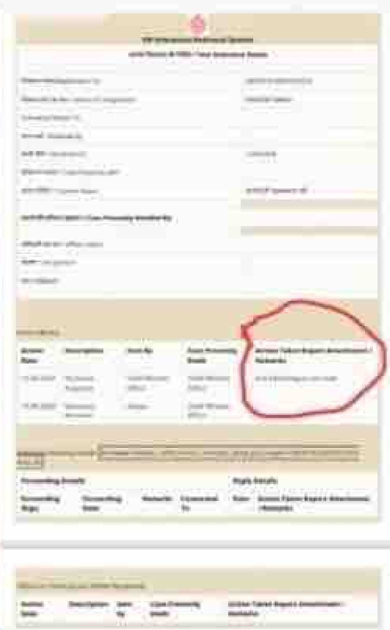

दुमछल्ला।

-हरियाणा सरकार ने परविंदर सिंह चौहान के नाम की शिफारिश पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने के लिए की है जिस पर अभी विधिवत नोटिफिकेशन होना है। 'गुस्ताखी माफ हरियाणा' उन्हें अग्रिम बधाई देता है